damages, how much has been paid to the farmers under these schemes, statewise, during the year for which figures are available?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House on receipt.

Gift of Irradiated Milk Powder

1379. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any quantity of irradiated milk powder got entry into the country by official or other sources;

(b) whether any school children have had the gifts of such irradiated milk powder from certain doner organisation; and

(c) if so, what action has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) Government has not received any information regarding entry of irradiated milk powder into the country, which is unfit for human consumption.

देश में दूध का उत्पादन

1380. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में दूध के उत्पादन के संबंध में दिनांक 3 जुलाई, 1987 को 'नवभारत टाइम्स' और 19 जून, 1987 के 'जनसत्ता' में प्रकाशित क्रमश: "भारत में तथाकथित श्वेत क्रांति एक सफेद झूठ है" और "ज्यादा दूध के लिए मिलने वाली मदद खटाई में" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या सरकार पशु विकास योजना/परियोजनाओं और डेरी विकास के संबंध में संसद सदस्यों की एक समिति गठित करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) और (ख) जी, हा । यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) तथा विश्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए सलाहकारों में एक संयुक्त शिष्टमंडल ने आपरेशन फ्लड–2 परियोजना की संवीक्षा करने तथा आपरेशन फ्लड–3 नामक नई परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए जुलाई–अगस्त, 1986 में भारत का दौरा किया । यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने सूचित किया है कि सलाहकारों द्वारा अध्ययन किए जाने का उद्देश्य आपरेशन फलड का समग्र रूप से मूल्यांकन करना नहीं था अपितु परियोजना के उन्हीं विशिष्ट पहलुओं का जायजा लेना था जहां नई परियोजना तैयार करने के लिए जानकारी पर्याप्त नहीं समझी गई थी ।

चूंकि मसौदा रिपोर्टों से यह पता चलता है कि सलाहकारों के विचार वित्तीय संस्थानों के सरकारी दृष्टिकोण को निश्चित रूप से नहीं दर्शाते अत: भारत सरकार ने इस मामले पर कोई कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं समझा । तथापि, ऐसे संकेत मिले हैं कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय/विश्व बैंक आपरेशन फलड–3 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।